भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2575

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशी व्यापार समझौते और रुपया व्यापार

2575. **श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:**
श्री मनोज तिवारी:
डॉ. हेमांग जोशी:
डॉ. के. सुधाकरः
श्री बलभद्र माझी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूके और ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) संपन्न करने की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है तथा इन समझौतों से भारत के सेवा निर्यात में किस प्रकार वृद्धि होगी:

(ख) सरकार किस प्रकार आरबीआई के साथ रुपया व्यापार निपटान तंत्र को बढ़ावा **दे** रही है तथा उस का अनुसरण कर रही है तथा अधिक साझेदार देशों को एसआरवीए खोलने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) फिनटेक, भू-स्थानिक सेवाओं और एवीजीसी जैसे क्षेत्रों में सेवा निर्यात को बढ़ाने के लिए उपयोग की जा रही रणनीतियाँ और 2026 तक के लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) विभिन्न एफटीए **के** अंतर्गत निर्यातकों को टैरिफ रियायतों तथा मूल नियमों के संबंध में वास्तविक समय पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के उपयोग में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने दिनांक 24 जुलाई, 2025 को व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। लागू होने के बाद, भारत-यूके सीईटीए आईटी/आईटीईएस, व्यावसायिक सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य परिर्चचा जैसे विभिन्न सेवा क्षेत्रों में पूर्वानुमानित, उन्मुक्त और अनुकूल बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह सेवा प्रदाताओं के अस्थायी आवागमन के लिए एक संरचित फेमवर्क भी तैयार करता है। व्यापारिक आगंतुक, संविदात्मक सेवा प्रदाता और स्वतंत्र पेशेवर स्पष्ट और पूर्वनिर्धारित अस्थायी प्रवेश और प्रवास नियमों के तहत ब्रिटेन में प्रवेश कर सकेंगे। एफटीए के साथ लागू होने वाला डबल कान्ट्रीट्यूशन कन्वेशंन सामाजिक सुरक्षा अंशदान के दोहरे भुगतान से बचने का एक तंत्र प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इन प्रावधानों के तहत प्रति वर्ष 1,800 तक भारतीय शैफ, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार ब्रिटेन में कार्य कर सकेंगे। जून 2022 में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता औपचारिक रूप से पुनः शुरू होने के बाद, अक्टूबर 2025 तक वार्ता के चौदह दौर पूरे हो चुके हैं। दिनांक 3 से 9 दिसंबर 2025 तक विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों में, दोनों पक्षों ने सेवाओं सहित विभिन्न वार्ता क्षेत्रों में हासिल की गई स्थिर प्रगति पर ध्यान दिया और इस गति को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

(ख): भारत से निर्यात पर जोर देते हुए वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये (आईएनआर) में वैश्विक व्यापार समुदाय की बढ़ती रुचि का समर्थन करने के लिए, भारतीय रुपये में

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान संबंधी अधिकृत व्यक्तियों (निर्देशों/डीलर सूचना/रिपोर्टिंग) श्रृंखला (ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 10 दिनांक 11 जुलाई, 2022, के माध्यम से निर्यात/आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 08 दिनांक 05 अगस्त, 2025 के अनुसार, अधिकृत डीलर बैंकों को अब रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगे बिना विदेशी अभिकर्ता बैंकों के विशेष रुपों वोस्त्रो खाते (एसआरवीए) खोलने की अनुमति है। इसके अलावा, भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान संबंधी ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 14, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 के अनुसार, एसआरवीए अधिशेष राशि को अब किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड और वाणिज्यिक पत्रों में भी निवेश किया जा सकता है।

(ग): वित्तीय सेवाओं सहित सेवाओं का निर्यात द्विपक्षीय समझौतों और मुक्त व्यापार समझौतों का एक प्रमुख घटक है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (एनजीपी), 2022 में भू-स्थानिक सेवाओं की वृद्धि की परिकल्पना की गई है, जिसमें भारत के समग्र डिजिटल सेवा निर्यात में उनका योगदान भी शामिल है। इस नीति का उद्देश्य नवाचार, बेहतर डेटा उपलब्धता, निजी क्षेत्र की भागीदारी और क्षमता विकास के लिए एक अनुकूल फ्रेमवर्क तैयार करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भू-स्थानिक इकोसिस्टम का निर्माण करना है। एनजीपी 2022 के अनुसार, भू-स्थानिक सेवाओं और उनकी निर्यात क्षमता के विस्तार के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, डेटा फ्रेमवर्क और संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु वर्ष 2025 और 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद अप्रैल 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एवीजीसी संवर्धन कार्य बल का गठन किया गया था। इस कार्य बल ने उद्योग और सरकार को एक साथ लाकर यह रूपरेखा तैयार की कि भारत एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र में कौशल, रोजगार और निवेश को कैसे बढ़ा सकता है; और देश को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। इस कार्य बल ने दिसंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राष्ट्रीय एवीजीसी मिशन, उत्कृष्टता केंद्र, मजबूत बुनियादी ढांचा और भारतीय बौद्धिक संपदा और निर्यात के लिए समर्पित सहयोग की सिफारिश की गई। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आईआईसीटी) मुंबई की स्थापना की गई है और इसे एक विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, प्रतिभाओं को विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) 2025 का आयोजन मई 2025 में संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक वैश्विक प्लेटफार्म के रूप में किया गया था।

(घ): ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफ़ॉर्म पर टैरिफ एक्सप्लोरर सेवा विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) के तहत पात्र भारतीय निर्यातों के लिए उपलब्ध टैरिफ रियायतों की जानकारी प्रदान करती है। इसमें उक्त टैरिफ रियायतों का लाभ उठाने के लिए अनुपालन किए जाने वाले उत्पत्ति नियमों का विवरण भी दिया गया है। यह सूचना खोजने योग्य के रूप में उपलब्ध है, जिसमें निर्यातकों के पास गंतव्य देश द्वारा उत्पाद को दिए गए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड या उत्पाद विवरण के आधार पर खोज करने का विकल्प होता है। निर्यातकर्ता खोज के आधार पर अपने उत्पादों से सबसे मिलते-जुलते उत्पादों का चयन कर सकते हैं और शुल्क एवं उत्पत्ति नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकृत स्रोतों से नई सूचना प्राप्त होते ही डेटाबेस को अद्यतन किया जाता है

****